special factors relating to the ISS. The first batch of direct recruits to Grade IV of ISS appointed in 1968 were placed below the Initial Constitution/ Maintenance stage appointees in that Grade. Direct recruits to Grade IV between 1968 and 1980 (Examinations 1967 to 1979) were promoted to Grade III (STS) between 1974 and 1983. Then an important change took place. Implementing the orders of the Hon'ble Supreme Court, dated 11.2.86, in Narendra Chadha's case, a large number of ad hoc appointees were appointed to Grade IV and were given retrospective seniority from dates of continuous officiation. This led to the direct recruits being assigned later dates of seniority in the revised Grade IV seniourity list. As directed by the Hon'ble Supreme Court, the promotions to Grade III made between 1974 and 1983 were also reviewed on the basis of the revised seniority list and a fresh promotion list was prepared. This resulted in the direct recruits, earlier promoted to Grade III from certain dates, being cither given later dates of promotion to Grade III or retained in the Grade IV seniority (but protected from reversion from Grade III etc. posts held by them). Further promotions were made to Grade III between 1986 and 1989 and to JAG between 1986 and 1988 on the basis of the revised Grade IV and Grade III seniority lists. But during the period September 1989 to April 1992, cases for regular promotion to Grade III and JAG could not be processed due to orders of the Hon'ble Central Administrative Tribunal, Delhi Bench and the Hon'ble Supreme Court in Pratap Narain's case. Ad hoc promotions to serving officers were allowed by the Hon'ble Supreme Court in August 1991 and these have been made.

सांख्यिकीय सेवा संवर्ग की समीक्षा

2785. श्रीमती सत्या बहिन: क्या प्रधान मंत्री 3 अगस्त, 1992 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 2635 को दिये गये उत्तर देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय सांख्यिकीय सेवा की संवर्ग-समीक्षा के पहलू पर विचार करने के लिए गठित किए गए "कृतिक बल" के प्रतिवेदन में क्या-क्या सुझाव दिये गये हैं;

(ख) भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में सांख्यिकीय सेवा के ग्रेडवार कितने-कितने पद उपलब्ध हैं और क्या 15.11.92 को ये पद रिक्त नहीं थे; यदि नहीं, तो 15.11.92 को मंत्रालयवार कितने पद रिक्त थे तथा इन पदों को किस निश्चित तिथि तक भर दिया जायेगा;

(ग) क्या सरकार सांख्यिकीय सेवा संवर्ग की समीक्षा करने का विचार रखती है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त समीक्षा कब तक किए जाने की सम्भावना है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री और गैर पारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखराम): (क), (ग) और (घ) "कृतिक बल" ने मसौदा रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जिसमें इसने अन्य बातों के साथ-साथ पदों का दर्जा बढ़ाने सहित भारतीय सांख्यिकीय सेवा की संवर्ग संरचना के बारे में निम्नानुसार सुझाव दिये हैं:—

क्रम सं०	ग्रेड (वेतनमान)	स्वीकृत संख्या	सुझाई गई संख्या
1	2	3	4
1	उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड (एच०ए०जी०) (7300—7600 रु०)	1	39
2.	वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (एच०ए०जी०) (5900—6700 रु०)	9	
3.	कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (जे०ए०जी०) (3700—5000 रु०)	116*	152

* इनमें से 40 पद गैर प्रकार्यात्मक चयन ग्रेड (एन०एफ०एस०जी०) (4500-5700 रु०)के रूप में संचालित है।

1	2	3	4
4.	ग्रेड III (3000—4500 रु०) (एस०टी०एस०)	143	245
5.	ग्रेड IV (2200—4000 रु०) (जे०टी०एस०)	260**	94
		529	530

** इनमें प्रतिनियुक्ति, अवकाश और प्रशिक्षण रिजर्व के 73 पद शामिल नहीं है।

कृतिक बल ने भारतीय सांख्यिकीय सेवा में सांख्यिकी/इलैक्ट्रोनिक संपर्क विधायन कार्य करने वाले कुछ पदों का संवर्गीकरण करने का सुझाव दिया है।

जहां तक संवर्ग समीक्षा का सम्बन्ध है, संवर्ग समीक्षा का कार्य प्रशासनिक व्यय को कम करने के लिए पदों को कम करने हेतु प्रयासों के सन्दर्भ में निर्देशों को ध्यान में रखते हुए कुछ समय के लिए रोक दिया गया है। इन *परिस्थितियों में यह संकेत देना सम्भव नहीं है कि कब* तक सपग्र संवर्ग समीक्षा का कार्य पूरा कर लिया जाएगा।

(2) भारतीय सांख्यिकीय सेवा की ग्रेडवार संवर्ग संख्या ऊपर दी गई है। मंत्रालयवार रिक्तियों की स्थिति संलग्न विवरण में दी गयी है (नीचे देखिए) इनमें से कुछ पद तदर्थ आधार पर भरे गये हैं। इन रिक्तियों को नियमित आधार पर भरने के लिए कार्यवाही की जा रही है।

विवरण

मंत्रालयवार रिक्तियां

क्रम सं०	मंत्रालय/विभाग	रिक्तियां
1	2	3
1.	शहरी विकास मंत्रालय	1
2.	कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय	14
3.	ग्रामीण विकास मंत्रालय	1
4.	पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवन मंत्रालय	4
5.	इस्पात और खान मंत्रालय	5
6.	ऊर्जा मंत्रालय	1
7.	वित्त मंत्रालय	6
8.	मानव संसाधन विकास मंत्रालय	2
9.	जल संसाधन मंत्रालय	15
10.	भूतल परिवहन मंत्रालय	1
11.	संचार मंत्रालय	1
12.	वाणिज्य मंत्रालय	10
13.	उद्योग मंत्रालय	5
14.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	15
15.	श्रम मंत्रालय	9
16.	प्रतिरक्षा मंत्रालय	5
17.	योजना मंत्रालय	101
18.	गृह मंत्रालय	9
19.	उर्वरक विभाग	1

Targets for installing Pumpsets in A.P.

2786. DR. YELAMANCHILI SIVAJI: ; Will the Minister of PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION be pleased to state:

(a) what is the target fixed for Andhra Pradesh for installing pumpsets in the State, during the current year; and

(b) what is the total cost involved therein and the resources sought to be mobilised?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES (SHRI SUKH RAM): (a) and (b) Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Increase in Employment Opportunities

2787. SHRI SURESH PACHOURI: Will the Minister of PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION be pleased to state:

(a) what has been the gap between the addition to the labour force and increase in employment opportunities at the end of the Sixth and Seventh Five Year Plan; and

(b) the backlog of unemployment at